(ग) इस प्रकार के अवैध कारखानों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

Payment of minimum wages to women workers

353. PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state;

fa) whether Governments attention has been drawn to the report of the National Commission on Self-Employed Women in the informal work sector;

(b) whether Government Departments and Undertakings have, been defaulters in respect of payment of minimum wages' to such working women; and

(c) if so, what steps are ceing taken to bring the offenders to book?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBEY): (a) Yes, Sir.

(b) No. Sir. No such complaint has been received by the Central Government.

(c) Does not arise.

आदिवासी क्षेत्रों में चलती-फिरती दुकानें

359. **श्री अजीत जोगी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पहुंच विहीन आदिवासी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए "चलती फिरती दुकानों" की कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय के समाचार प्राप्त हुए हैं कि आदिवासी क्षेत्र और जनसंख्या को देखते हुए ऐसी "चलती-फिरती दुकानों" की संख्या अत्यंत कम है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार इन "चलती फिरती दुकानों" की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना के प्रशासन तथा कार्या-वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की होती है । तथापि, केंद्रीय सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए है, जिनमें उनसे कहा गया है कि वे दूरदराज के इलाकों, दुर्गम क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों तथा जिन क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें नहीं है और जहां उनकी संख्या कम है, वहां चलती-फिरती उचित दर की दुकानें चलाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करें। एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्कीम भी है, जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के वास्ते चलती-फिरती दुकानें चलाने हेतु वाहन क्रय करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1985–86 से 1987–88 के दौरान केंद्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 177 वाहन क्रय करने के लिए 397.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी है ।

चार्ल्स कोरिया समिति के सुझावों का कार्यान्वयन

360. **श्री अजीत जोगी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा महानगरों की समस्याओं पर विचार करने के लिए गठित की गई चार्ल्स कोरिया समिति